पर पुलों और बांधों का निर्माण करायें तभी प्रतापगढ़ जिले का विकास हो सकता है।

(ii) REPORTED FIRING ON THE WORKERS OF BHARAT HEAVY ELECTRICALS LTD., HARDWAR.

SHRI KRISHNA CHANDRA HALDER (Durgapur) : Mr. Speaker, Sir, under Rule 377 I want to mention about a very serious matter on the Floor of the House and would request the hon'ble Minister to make a statement thereon.

Sir, a serious situation has arisen out of the indiscriminate firing by CISF on the workers of Bharat Heavy Electricals Ltd., Hardwar on 23-3-1978. The CISF without any provocation attacked with firearms on the unarmed peaceful workers and killed and injured many of them including Secretaries of the CITU and AITUC unions. Within the very short period, more than 20 workers fell down with bullet injuries and hundreds were limping into blocks with major with major injuries. The fire brigade and ambulance started rushing dozens of injured and wounded to the hospital. The top management was nowhere in the scene and they were busy in holding a meeting to discuss the situation. Nearly after three hours the Executive Director, Mr. Wahi announced over intercom the withdrawal of CISF personnel and handing over the factory to the local police. Following the incident a large number of workers are being rounded up by police on various false charges. This has further worsened the situation.

Sir, I demand withdrawal and abolition of CISF and order for judicial enquiry so that culprits may be punished.

Sir, the CISF is under Home Ministry and BHEL, Hardwar is a public undertaking. Through you, Sir, I would request the concerned Ministers to make a statement on the Floor of the House as early as possible.

(iii) BOUNDRY DISPUTE BETWEEN KARNATKA AND MAHARASHTRA.

श्री केशव राव सोंडगे (नांदेड़) : दस लाख मराठी लोगों का मसला मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। कर्नाटक और महाराष्ट्र के अन्दर बेलगाम कारवार, नापानी, बालकी, सन्तपुर, औरड़, हुमनाबाप आदि दस लाख मराठी लोग हैं। वहां पर कर्नाटक में इन पर बहुत जुल्म हो रहा है। उन लोगों ने हर तरह से, चुनाव में तथा दूसरे तरीकों से अपने खयालात का इजहार किया है। इसके बावजूद सेंट्रल गवर्नमेंट उनकी मदद करने के लिए, उनको इंसाफ देने के लिए तैयार नहीं है। हमने बर्मा देश के साथ अपने बाउंडरी डिस्प्यूट को हल कर लिया है, बंगला देश के साथ हल कर लिय है। लेकिन अपने ही देश में दो राज्यों के बीच जो सीमा विवाद है उस सीमा विवाद को लोकशाही के तरीकों के अनुसार हल करने के लिए हम तैयार नहीं हैं। मैं जानना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार अभी तक उन से कितनी और कुर्बानियां मांगती है, कौन सी स्ट्रगल वह चाहती हैं कि वे करें, कितने और उन लोगों में शहीद हों ताकि उसकी आंख खुल सके और वह इस सवाल को हल कर सके ? प्रधान मंत्री से मैं गुजारिश करूंगा कि वह इसको देखें। उनको बैलगांव के और कितने लोग शहीद चाहिये ? कब वह उनको इंसाफ दे सकेंगे ? मैं मानता हूं कि पहले कांग्रेस सरकार थी, इंदिरा गांधी का राज्य था। वह सरकार लोगों को इंसाफ नहीं देती थी। लेकिन हमने चुनाव के अन्दर लोगों से वादे किए हैं कि हम उनको इंसाफ देंगे। मैं प्रधान मंत्री से गुजारिश करता हूं कि इस मसले पर वह खामोश न बैठें रहें। लोगों के जजबात को देखें, उनको इंसाफ दें। कई कमीशन बैठे हैं, कई चीफ मिनिस्टर तबदील हुए हैं, कई हकूमतें तबदील हुई हैं, कई प्रधान मंत्री बने हैं, इनक्लाब हुआ है लेकिन इस मसले को हल नहीं किया गया है। इतना ही नहीं कर्नाटक एकीकरण समिति के छः मंपांच नुमाइंदे चुन कर आए हैं। उनका कहना है कि जम्हूरियत की इन बीस बाईस सालों की लड़ाई ने यह साबित कर दिया है कि हमारी मांग बिल्कुल जायज है। रेलवे मिनिस्टर साहब प्रो० दंडवते ने फरमाया था कि जनता पार्टी का राज्य हो जाएगा तो